

अमित शाह ने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई , पेपर लीक समाप्त करने की प्रशंसा की

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आरपीए में आयोजित समारोह में आठ हजार नवनि्युक्त कांस्टेबलों को नियुक्त पत्र दिए

जयपुर, 1० जनवरी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पारदर्शी तरीके से लोकसेवकों की भर्ती करने से ही कोई प्रदेश आगे बढ़ सकता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार का पेपरलीक का सिलसिला खत्म कर राजस्थान को इससे निजात दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मजबूत व कुशल नेतृत्व मिल रहा है।**

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए भ्रष्टाचार का उन्मूलन और योग्यता का सम्मान करते हुए राजस्थान के युवाओं को 'बिना सिफारिश और बिना खर्च' के नौकरी दे रही है।

शाह शनिवार को आरपीए में कांस्टेबल नव नियुक्त समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी कानून व्यवस्था से ही प्रदेश का विकास संभव है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पेपरलीक पर रोक लगाने के साथ-साथ



केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को आरपीए में आयोजित कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह को संबोधित किया।

कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को पूरे देश में निवेश का अग्रणी राज्य बनाने का काम भी किया है। इसी का परिणाम है कि आज देशभर के निवेशक राजस्थान की ओर आने की स्पर्धा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मजबूत और कुशल नेतृत्व मिल

रहा है। धारा 37० को हटकर जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ते हुए देश की एकता एवं अखंडता को मजबूती देने का काम किया गया। शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद का सफाया करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया।

शाह ने कार्यक्रम में संकेतिक रूप से 1० आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में 8 हजार से अधिक आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए

गए। इससे पहले उन्होंने भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में बने मल्टी परपज इंडोर हॉल का वर्चुअल लोकार्पण किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदू म, सांसद मदन राठौड़, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित जनप्रतिनिधिगण, पुलिस अधिकाीरगण, बड़ी संख्या में नव नियुक्त कांस्टेबल एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

ट्रंप ने ईरान में सैन्य हस्तक्षेप के संकेत दिए परन्तु ट्रंप ने यह भी कहा कि वह जमीन पर सैनिक नहीं उतारेंगे

वॉशिंगटन, 1० जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि अगर ईरान वर्तमान अशांति के इस दौर में लोगों को मारना शुरू कर देता है तो अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा, हालांकि वह जमीन पर अपने सैनिकों की नौतानी नहीं करेगा।

ईरान की स्थिति पर संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं, तो ऐसा होने पर अमेरिका अपनी भूमिका निभायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका अपनी फौजें, ईरान की जमीन पर उतार देगा। इसका अर्थ यह है कि उन्हें वहां बहुत जोर से मारना है, जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। ट्रम्प और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने

- ट्रंप ने कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही जनता पर हमला किया गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा।**

बार-बार चेतावनी दी है कि यदि ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है, तो वॉशिंगटन कार्रवाई करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अशांति के बारे में ट्रम्प प्रशासन की टिप्पणियों को हस्तक्षेपवादी और भ्रामक बताते हुए उनकी निंदा की थी। ईरान का कहना है कि ये बयान ईरानी लोगों के प्रति अमेरिका की निरंतर शत्रुता को दर्शाते हैं।

एसआई भर्ती ...

गुहार की थी। एकलपीठ ने तीस अक्टूबर, 2०25 को इन अर्थर्थियों को भर्ती में तीन साल की छूट देने को कहा। वहीं राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर गत 13 नवंबर को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी।

छाव को नुकसान पहुंचाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्लंटकों और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में—जहाँ भारत निर्यात बढ़ाने की उम्मीद करता है—नीतिगत स्पष्टता लागत प्रतिस्पर्धा जितनी ही महत्वपूर्ण है। उद्योग संगठनों का मानना ​​​​है कि चरणबद्ध या सीमित व्यापार समझौता एक व्यावहारिक रास्ता हो सकता है। शुल्क युक्तिकरण, मानकों की पारस्परिक मान्यता और विवाद निपटने पर केन्द्रित प्रारंभिक सौदे' सौदे निर्यातकों को त्वरित राहत दे सकते हैं और बाद में एक व्यापक समझौते के लिए भरोसा भी बना सकते हैं।

आखिरकार, निर्यातक जोर देते हैं कि निष्क्रियता से होने वाले नुकसान की लागत लगातार बढ़ रही है। मुनाफे के मार्जिन घट रहे हैं और प्रतिस्पर्धी तीव्र हो रही है—हर तिमाही की देरी का मतलब है ऑर्डर और जमीन खो देना। एक निर्यातक ने कहा, व्यापार समझौते अब प्रतीकात्मक नहीं रहे; वे हमारे अस्तित्व का सवाल बन चुके हैं। भारत और अमेरिका के लिए, एक व्यापार समझौता न केवल द्विपक्षीय व्यापार को स्थिर करेगा, बल्कि वैश्विक बाजारों को भी एक सशक्त संकेत देगा। ज़मीनी स्तर पर निर्यातकों के लिए, यह टिके रहने और पिछड़ जाने के बीच का अंतर हो सकता है।

पुणे निगम चुनाव के लिए सुप्रिया व अजित पवार ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया

मुंबई, 1० जनवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष अजीत पवार और राकांपा (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शनिवारको पुणे के शिवाजीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में आगामी नगर निगम चुनावों के लिए अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी

- भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के सदस्य होने के बाद भी अजित पवार ने केन्द्र व राज्य सरकार की आलोचना की**

किया। इस संयुक्त घोषणापत्र में पुणे में मुप्त मेट्रो और बस यात्रा का वादा किया गया है।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, “पुणेवासी सवाल कर सकते हैं कि क्या मुफ्त मेट्रो और बस यात्रा संभव भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह संभव है। हमने विशेषज्ञों से बात करने के बाद इस में फैसला किया है। हम पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ के निवासियों को मुफ्त मेट्रो रेलवे और बस यात्रा प्रदान करेंगे।”

घोषणापत्र में पुणे नगर निगम के स्कूलों के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने के साथ-साथ पुणे में 15० मॉडल स्कूल स्थापित करने का वादा किया गया है।

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, “पुणे के पांच साल के विकास का मुद्दा हमारे सामने है। मुफ्त यात्रा प्रदान करना संभव है। क्योंकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के प्रशासन में कुछ गलतियां हैं, जिन्हें दूर किया जाएगा।”

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिठ्ठी लिखी

कोलकाता, 1० जनवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान आम नागरिकों के साथ किए जा रहे निरंतर उल्टीड़न पर हैरानी और पीड़ा व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में आरोप लगाया है कि इस पुनरीक्षण अभ्यास के कारण 77 मौतें, आत्महत्या के चार प्रयास और कम से कम 17 लोगों के बीमार होने व अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जी.एस.टी. आज की कामकाज से जुड़ी कई कमियों से जूझ रहा है। रिफंड मिलने में देरी, नियमों का जटिल पालन और केन्द्र व राज्यों के बीच बार-बार होने वाले मतभेदों, खासकर छोटे कारोबारियों के लिए ये समस्याएं नकदी की कमी और प्रशासनिक थकाण का कारण बनती हैं। इन अड़चनों को दूर किए बिना और ज्यादा बदलाव करने से प्रेरित होने के बजाय आकांक्षा से प्रेरित है और इसमें कुछ सच्चाई भी है। भारत की जनसंख्या संरचना, बढ़ता घरेलू बाजार और डिजिटल ढांचा मजबूत आधार देते हैं। लेकिन केवल आकांक्षा से संस्थागत तैयारी की कमी्री नहीं हो सकती। जिला प्रशासन, नगर निकाय और राज्य नियामक, जो सुधारों को ज़मीन पर लागू करते हैं, अक्सर स्टाफ, विशेष कौशल और डिजिटल क्षमता की कमी से जूझते

हैं। तेज़ सुधार निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन श्रम बाजार में वैधता और स्वीकार्यता भी ज़रूरी है। भरोसेमंद सुरक्षा, परामर्श और अमल की क्षमता के बिना ये सुधार एक्टरफा माने जा सकते हैं, भले ही उनका मकसद समावेशी विकास (इन्क्लुसिव ग्रोथ) और रोजगार सृजन हो।

सरकार कुछ हद तक सही संकेत देती है कि यह सुधार चक्र संकट से प्रेरित होने के बजाय आकांक्षा से प्रेरित है और इसमें कुछ सच्चाई भी है। भारत की जनसंख्या संरचना, बढ़ता घरेलू बाजार और डिजिटल ढांचा मजबूत आधार देते हैं। लेकिन केवल आकांक्षा से संस्थागत तैयारी की कमी्री नहीं हो सकती। जिला प्रशासन, नगर निकाय और राज्य अधिसूचित नहीं करने से इसका अमल रुका हुआ है, जो राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलताओं को दर्शाता

कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया

नयी दिल्ली, 1० जनवरी। कांग्रेस ने मनरेगा की जगह नया कानून लाने के मोदी सरकार के कदम को रोजगार की इस महत्वपूर्ण योजना पर बुलडोजर चलाना करार दिया और कहा कि पार्टी ने इसके खिलाफ पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू कर दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को यहां एक बयान में कहा कि “कांग्रेस ने आज देशभर के प्रत्येक जिला इकाई के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ मनरेगा बचाओ संग्राम को शुरूआत कर दी। कांग्रेस इस संघर्ष को निर्णायक परिणाम तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार द्वारा जब तब मनरेगा पर बुलडोजर चलाकर छीने गए काम के अधिकार, आजीविका और जवाबदेही को पूरी तरह बहाल नहीं करा लिया जायेंगे इसके लिए फिलहाल इकाई रखागे।” कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल में पारित वीबी-जी राम जी एक्ट के रूप में आये नये कानून से मनरेगा की मूल भावना खत्म हो गई है। अब काम की गारंटी कानूनी अधिकार नहीं रह गई बल्कि केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर हो गई है। मनरेगा खत्म करने से ग्राम पंचायतों की ताकत बहुत कमजोर हुई है और मजदूरी की गारंटी तथा समय पर भुगतान पर सवाल उठ रहे हैं।

देवली में तीन करोड़ रूपए का गांजा जब्त

- पुलिस ने नाकाबंदी कर उड़ीसा से आ रहे ट्रूक में 500 किलो गांजा पकड़ा।**

किया है। देवली पुलिस थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, पुर्बेन्द्र सोलंकी और डीएसपी हेमराज के सुपरविजन में उपनिरीक्षक ओमप्रकाश की टीम ने देवली हाईवे पर घेराबंदी की थी। इसी के चलते पुलिस को देखते ही तस्करी ने ट्रक को टोंक की ओर भगाकर ले जाने की कोशिश

किया। इस संयुक्त घोषणापत्र में पुणे में मुप्त मेट्रो और बस यात्रा का वादा किया गया है।

ईरान में खामनेई विरोधी प्रदर्शनकारियों पर मशीनगन से गोलियां चलाईं

गोलीबारी में 217 प्रदर्शनकारी मारे गये, सरकार विरोधी आंदोलन और उग्र हुआ

- अगर मृतकों की संख्या की सही पुष्टि हो जाती है, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि सरकार 28 दिसंबर से सड़कों पर उतर रहे प्रदर्शनकारियों को मारती है, तो उसे इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।**

है। प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर स्थानीय डॉक्टर ने बताया कि मृतकों में अधिकतर युवा थे, जिनमें उत्तरी तेहरान के एक पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करने के दौरान मारे गए कई लोग शामिल थे। इन सभी

की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, वाशिंगटन डीसी स्थित ह्यूमन राइट्स एंक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी, जो सिर्फ पहचाने गए पीड़ितों की गिनती करती है, उसमे विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से अब तक कम से कम 63 मौतों की पुष्टि की है।

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिठ्ठी लिखी

- बनर्जी ने नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, क्रिकेटर मोहम्मद शमी, फिल्म एक्टर व सांसद दीपक अधिकारी जैसी कई हस्तियों का मुद्दा उठाया, जिन्हें चुनाव आयोग के सामने अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होगी।**

- मुख्यमंत्री ने टाइप की हुई चिठ्ठी के साथ एक हस्तालिखित नोट भी भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि “मुझे” पता है आप ना तो जवाब देंगे ना ही स्पटीकरण देंगे पर विवरण देना मेरा कर्तव्य है।**

है। उन्होंने कहा, "ये घटनाएं डर, डराने-धमकाने और अवैधिक कार्यकां का परिणाम

प्र.मंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों ...

है। तेज़ सुधार निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन श्रम बाजार में वैधता और स्वीकार्यता भी ज़रूरी है। भरोसेमंद सुरक्षा, परामर्श और अमल की क्षमता के बिना ये सुधार एक्टरफा माने जा सकते हैं, भले ही उनका मकसद समावेशी विकास (इन्क्लुसिव ग्रोथ) और रोजगार सृजन हो।

सरकार कुछ हद तक सही संकेत देती है कि यह सुधार चक्र संकट से प्रेरित होने के बजाय आकांक्षा से प्रेरित है और इसमें कुछ सच्चाई भी है। भारत की जनसंख्या संरचना, बढ़ता घरेलू बाजार और डिजिटल ढांचा मजबूत आधार देते हैं। लेकिन केवल आकांक्षा से संस्थागत तैयारी की कमी्री नहीं हो सकती। जिला प्रशासन, नगर निकाय और राज्य नियामक, जो सुधारों को ज़मीन पर लागू करते हैं, अक्सर स्टाफ, विशेष कौशल और डिजिटल क्षमता की कमी से जूझते

हैं। तेज़ सुधार निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन श्रम बाजार में वैधता और स्वीकार्यता भी ज़रूरी है। भरोसेमंद सुरक्षा, परामर्श और अमल की क्षमता के बिना ये सुधार एक्टरफा माने जा सकते हैं, भले ही उनका मकसद समावेशी विकास (इन्क्लुसिव ग्रोथ) और रोजगार सृजन हो।

है। तेज़ सुधार निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन श्रम बाजार में वैधता और स्वीकार्यता भी ज़रूरी है। भरोसेमंद सुरक्षा, परामर्श और अमल की क्षमता के बिना ये सुधार एक्टरफा माने जा सकते हैं, भले ही उनका मकसद समावेशी विकास (इन्क्लुसिव ग्रोथ) और रोजगार सृजन हो।

महाराष्ट्र में नए समीकरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीट बंटवारे में भी सहयोगी दलों की वास्तविक ताकत झलकती है। शिवसेना (यूबीटी) 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मनसे 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) इस एग गठबंधन के तहत केवल 1० सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की घोषणा के लिए हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे भाइयों ने मराठी मानूस को एक सशक्त संदेश देते हुए कहा, बंटेंगे तो कटेंगे, यानी बंटें तो हारेंगे, एकजुट रहे तो जीतेंगे। यह नारा उन्होंने 2०24 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के इस्तेमाल किए गए नारे से प्रेरित होकर दिया।

भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) गठबंधन ने मराठी मानूस के बीच मजबूत पकड़ बना ली है। एस्केंडिया स्ट्रैटेंजीस के एक सर्वे के मुताबिक, इस समुदाय का वोट अब 44–42 प्रतिशत के अनुपात में बंट चुका है। वहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण उड़ब उठकर की पार्टी को जो मुस्लिम वोट मिला था, वह एमवीए से अलग होने के बाद स्वतः ठाकरे खेमे में आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।

इसके अलावा पवार परिवार के प्रतिद्वंद्वी भी धीरे-धीरे करीब आते दिख रहे हैं। एनसीपी (अजित पवार गुट) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइंट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: ०141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायया हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हथ्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स ०151-2522737। अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:०145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्दस्टीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422,226423, फैक्स: ०2973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-2०1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: ०7469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: ०1562-256908